भारत सरकार

अंतरिक्ष विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3358

बुधवार, 09 अगस्त, 2023 को उत्तर देने के लिए

स्टार्टअप्स के विकास को बढ़ावा देना

3358. श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्टार्टअप्स के विकास को प्रोत्साहित करके भारत की अंतरिक्ष एजेंसी को और अधिक व्यापार अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि हाल के वर्षों में देश की सफलता दर लगभग 70 प्रतिशत है, जो 90 के दशक में अमरीका, यूरोप, रूस अथवा चीन के रॉकेटों की दरों की तुलना में खराब है; और

(घ) यदि हां, तो भारत की उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं का मूल्य वर्ष 2025 तक लगभग दोगुना होकर एक बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री

(डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) एवं (ख)

जी, हां। अंतरिक्ष के क्षेत्र में वर्ष 2020 में किए गए सुधारों एवं हाल ही में जारी भारतीय अंतरिक्ष नीति - 2023 के साथ, सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में आद्योपांत कार्यकलापों को आयोजित करने के लिए स्टार्टअप्स सहित गैर-सरकारी कंपनियों (एन.जी.ई.) को सक्षम बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

एन.जी.ई. के अंतरिक्ष कार्यकलापों को संवर्धित करने, ठोस सहायता प्रदान करने और प्राधिकृत करने के लिए एकल खिड़की एजेंसी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) का गठन किया है, जिसके माध्यम से इस संबंध में आवश्यकता

...2/-

सहायता प्रदान की जा रही है। इस संबंध में राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के माध्यम से आवश्यक तकनीकी सहायता, समर्पित सुविधाओं का उपयोग और मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है।

स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए इन-स्पेस द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं:

- इन-स्पेस बीज निधि योजना
- इसरो सुविधाओं के उपयोग के लिए मूल्य सहायता
- ठोस सहायता, प्रौद्योगिकी हस्तातंरण, आदि के मानदंड में एन.जी.ई. के लिए तकनीकी सहायता
- सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रयोगशाला की स्थापना
- संभावित व्यापार अवसरों के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय उद्योगों के साथ निरन्तर बैठकें/ प्रत्यक्ष बैठकें।

(ग) एवं (घ)

रॉकेट प्रक्षेपणों के लिए हाल के वर्षों (2017-2022 के बीच) में देश की सफलता दर लगभग 90% है, जिसकी समान अवधि के दौरान अंतरिक्ष के क्षेत्र में संलग्न अन्य राष्ट्रों की अर्थात् यूरोप (90%), यू.एस.ए. (97%), रूस (98%), चीन (94%) और जापान (91%) की सफलता दर के साथ तुलना की जा सकती है।

विगत दस वर्षों (2013-2022) के दौरान भारत ने 52 प्रक्षेपण किए हैं, इनमें मात्र 3 असफल रहे और सफलता दर 94.3% प्रतिशत रहा है।

प्रक्षेपण सेवा बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार एनसिल (अं.वि. के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम) के माध्यम से इसरो के प्रक्षेपण रॉकेट यथा – पी.एस.एल.वी. और एल.वी.एम.-3 के द्वारा वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करती है।

एनसिल ने भारतीय उद्योग के माध्यम से पी.एस.एल.वी. के निर्माण के लिए निजी संघ के साथ संविदा संपादित की है। आगे, इन-स्पेस ने लघु उपग्रह बाजार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हाल ही में वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवाओं हेतु इच्छुक भारतीय उद्योगों के लिए लघु उपग्रह प्रक्षेपण रॉकेट (एस.एस.एल.वी.) के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) जारी की है।

***